Academe *Journal of Education & Psychology* *ISSN: 2249-040X*
Volume-15, Issue-1, Year-2025 (January-June) *Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.25)*
PP: 387-397 *Journal Website www.academejournal.in*

सत्ता, पत्रकारिता और डिजिटल माध्यमों का नया संप्रेषण : लोकतांत्रिक विमर्श, जनमत निर्माण और सामाजिक मीडिया की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक अध्ययन

दर्शन सुधाकर

नेट

शोध-सारांश :–

इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक के बाद भारतीय लोकतंत्र में संप्रेषण की प्रकृति में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। पारंपरिक जनसंचार माध्यमों- जैसे समाचारपत्र, रेडियो और टेलीविजन के साथ-साथ सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और इंटरनेट आधारित पत्रकारिता ने सत्ता, समाज और नागरिकों के बीच संवाद की नई संरचना निर्मित की है। इस परिवर्तन ने राजनीति और पत्रकारिता दोनों की कार्यशैली को प्रभावित किया है। राजनीतिक दल अब केवल जनसभाओं और प्रचार अभियानों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप जैसे माध्यमों द्वारा सीधे नागरिकों तक पहुँच बना रहे हैं। दूसरी ओर पत्रकारिता भी पारंपरिक संपादकीय नियंत्रण से आगे बढ़कर डिजिटल प्रतिस्पर्धा, तात्कालिकता और वैकल्पिक सूचना-प्रवाह के दबाव में कार्य कर रही है।

यह शोधपत्र सत्ता और पत्रकारिता के बीच विकसित हो रहे नए संप्रेषण तंत्र का विश्लेषण करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि डिजिटल माध्यमों ने लोकतांत्रिक संवाद, जनमत निर्माण, राजनीतिक वैधता और मीडिया की भूमिका को किस प्रकार पुनर्परिभाषित किया है। शोध में गुणात्मक पद्धति का उपयोग करते हुए उपलब्ध साहित्य, समकालीन मीडिया प्रवृत्तियों, राजनीतिक अभियानों और डिजिटल पत्रकारिता की संरचनाओं का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया ने राजनीतिक सहभागिता को व्यापक बनाया है, किन्तु इसके साथ ही दुष्प्रचार, ट्रोल संस्कृति, फेक न्यूज़, कॉर्पोरेट प्रभाव और पत्रकारिता की निष्पक्षता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं।

मुख्य शब्द : सत्ता, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, डिजिटल संप्रेषण, लोकतंत्र, जनमत, मीडिया।

प्रस्तावना :–

मानव सभ्यता के विकास में संप्रेषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। समाज में विचारों, सूचनाओं और अनुभवों के आदान-प्रदान ने न केवल सामाजिक संरचनाओं को विकसित किया, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को भी स्थायित्व प्रदान किया। आधुनिक लोकतंत्र

© Copyright @ Authors

में पत्रकारिता को 'चौथा स्तंभ' कहा जाता है क्योंकि यह शासन और जनता के मध्य संवाद स्थापित करने का कार्य करती है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सूचना देना, जनमत का निर्माण करना, सत्ता की जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है। परंतु डिजिटल क्रांति और इंटरनेट आधारित संचार तकनीकों के विस्तार ने पत्रकारिता और सत्ता के संबंधों को नई दिशा प्रदान की है।

विगत वर्षों में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ा है। राजनीतिक दलों, नेताओं और सरकारी संस्थाओं ने इन्हें केवल प्रचार के माध्यम के रूप में नहीं, बल्कि जनसंपर्क, छवि निर्माण और वैचारिक विस्तार के उपकरण के रूप में अपनाया है। परिणामस्वरूप राजनीतिक संप्रेषण का पारंपरिक मॉडल परिवर्तित हुआ है। अब जनता केवल समाचारों की उपभोक्ता नहीं रही, बल्कि वह स्वयं सूचना-निर्माण, प्रतिक्रिया और विमर्श की सहभागी बन गई है। इस परिवर्तन ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अधिक गतिशील बनाया है, किन्तु साथ ही सूचना की विश्वसनीयता, मीडिया की स्वतंत्रता और पत्रकारिता की नैतिकता से जुड़े अनेक प्रश्न भी उत्पन्न किए हैं।

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में डिजिटल माध्यमों का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट की पहुँच में वृद्धि ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सूचना के नए नेटवर्क निर्मित किए हैं। राजनीतिक अभियानों में सोशल मीडिया की निर्णायक भूमिका स्पष्ट दिखाई देती है। चुनावी रणनीतियों, डिजिटल प्रचार, ऑनलाइन अभियानों और डेटा-आधारित राजनीतिक संप्रेषण ने लोकतंत्र के स्वरूप को प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त पत्रकारिता भी अब केवल संस्थागत मीडिया तक सीमित नहीं रही। स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल, नागरिक पत्रकारिता और वैकल्पिक मीडिया मंचों ने सूचना-व्यवस्था को बहुआयामी बना दिया है।

यद्यपि यह परिवर्तन लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा देता है, परंतु इसके नकारात्मक पहलू भी सामने आए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी समाचार, वैचारिक ध्रुवीकरण, ट्रोलिंग, नफरतपूर्ण भाषण और सूचना-हेरफेर जैसी समस्याएँ बढ़ी हैं। कई बार राजनीतिक शक्तियाँ डिजिटल माध्यमों का उपयोग जनमत को प्रभावित करने, विरोधी विचारों को कमजोर करने तथा प्रचार-प्रधान राजनीति को बढ़ावा देने के लिए करती हैं। ऐसे में पत्रकारिता की स्वतंत्रता और निष्पक्षता चुनौती के दौर से गुजर रही है।

यह शोधपत्र सत्ता और पत्रकारिता के नए संप्रेषण तंत्र का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें यह समझने का प्रयास किया गया है कि डिजिटल युग में राजनीतिक सत्ता और पत्रकारिता के

© Copyright @ Authors

संबंध किस प्रकार परिवर्तित हुए हैं तथा इन परिवर्तनों का लोकतंत्र और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है।

उपलब्ध साहित्य :–

संचार और पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने मीडिया और सत्ता के संबंधों का विश्लेषण किया है। हेरॉल्ड लासवेल ने संचार को सत्ता और समाज के मध्य प्रभाव निर्माण की प्रक्रिया के रुप में परिभाषित किया। उनके अनुसार संचार केवल सूचना का आदान-प्रदान नहीं, बल्कि राजनीतिक नियंत्रण और सामाजिक दिशा-निर्देशन का माध्यम भी है। मार्शल मैक्लुहान ने 'माध्यम ही संदेश है' की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया कि तकनीक केवल संदेशों को प्रसारित नहीं करती, बल्कि समाज की संरचना और चेतना को भी प्रभावित करती है।

युर्गन हैबरमास ने सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sphere) की अवधारणा के माध्यम से लोकतांत्रिक विमर्श में मीडिया की भूमिका को रेखांकित किया। उनके अनुसार स्वतंत्र और तार्किक संवाद लोकतंत्र की आधारशिला है। डिजिटल माध्यमों ने इस सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया है, किन्तु साथ ही बाज़ारवादी शक्तियों और राजनीतिक हस्तक्षेप ने इसकी निष्पक्षता को चुनौती भी दी है।

नोम चॉम्स्की और एडवर्ड हरमन ने 'प्रोपेगेंडा मॉडल' के माध्यम से यह बताया कि मीडिया संस्थाएँ आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के प्रभाव में कार्य करती हैं। उनका मत था कि कॉर्पोरेट स्वामित्व और राजनीतिक गठजोड़ मीडिया की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। वर्तमान डिजिटल पत्रकारिता के संदर्भ में यह दृष्टिकोण अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि सोशल मीडिया कंपनियाँ और डिजिटल एल्गोरिद्म सूचना के प्रवाह को नियंत्रित कर रहे हैं।

भारतीय संदर्भ में रामचंद्र गुहा, राजदीप सरदेसाई, विनोद दुआ, पुण्य प्रसून वाजपेयी तथा अन्य मीडिया विश्लेषकों ने लोकतंत्र और मीडिया के बदलते संबंधों पर विस्तृत चर्चा की है। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि सोशल मीडिया ने राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाया है, विशेष रुप से युवाओं के बीच। 2014 और 2019 के भारतीय आम चुनावों में डिजिटल प्रचार अभियानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक दलों ने डेटा विश्लेषण, आईटी सेल और सोशल मीडिया रणनीतियों के माध्यम से मतदाताओं तक पहुँच बनाने का प्रयास किया।

डिजिटल पत्रकारिता पर किए गए अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि ऑनलाइन मीडिया ने वैकल्पिक आवाज़ों को मंच प्रदान किया है। स्वतंत्र पत्रकार और नागरिक पत्रकारिता के माध्यम से अनेक ऐसे मुद्दे सामने आए, जिन्हें मुख्यधारा मीडिया पर्याप्त स्थान नहीं दे पा रहा था। हालांकि दूसरी ओर फेक न्यूज़ और सूचना-भ्रम की समस्या ने पत्रकारिता की विश्वसनीयता को प्रभावित

© Copyright @ Authors

किया है। व्हाट्सऐप विश्वविद्यालय, ट्रोल आर्मी और बॉट-आधारित प्रचार जैसे शब्द इसी डिजिटल युग की देन हैं।

कई शोधों में यह चिंता व्यक्त की गई है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों की तात्कालिकता ने पत्रकारिता के सत्यापन मानकों को कमजोर किया है। क्लिक-आधारित अर्थव्यवस्था और टीआरपी की प्रतिस्पर्धा में सनसनीखेज़ समाचारों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके कारण पत्रकारिता का सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रभावित होता है।

उपलब्ध साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सत्ता, पत्रकारिता और डिजिटल संप्रेषण के संबंधों पर गंभीर विमर्श आवश्यक है। वर्तमान शोध इसी आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास करता है।

शोध-प्रविधि :–

प्रस्तुत शोधपत्र में गुणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया है। अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इसके अंतर्गत पुस्तकों, शोध-पत्रों, समाचार आलेखों, डिजिटल मीडिया रिपोर्टों, सरकारी दस्तावेजों और ऑनलाइन स्रोतों का विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन की प्रविधि को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है -

- साहित्य समीक्षा पद्धति : मीडिया, सत्ता और डिजिटल संप्रेषण से संबंधित उपलब्ध साहित्य का विश्लेषण किया गया।
- विषय-वस्तु विश्लेषण : प्रमुख राजनीतिक अभियानों, सोशल मीडिया प्रवृत्तियों और डिजिटल पत्रकारिता की सामग्री का अध्ययन किया गया।
- तुलनात्मक अध्ययन : पारंपरिक पत्रकारिता और डिजिटल पत्रकारिता के स्वरूपों की तुलना की गई।
- व्याख्यात्मक पद्धति : डिजिटल संप्रेषण के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया।
- शोध का उद्देश्य किसी एक राजनीतिक दल या मीडिया संस्थान का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि डिजिटल युग में विकसित हो रही संप्रेषण प्रक्रियाओं को अकादमिक दृष्टि से समझना है।

© Copyright @ Authors

परिणाम एवं विमर्श–

1. डिजिटल युग में सत्ता का नया संप्रेषण–

डिजिटल तकनीक ने राजनीतिक सत्ता के संप्रेषण तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है। पहले राजनीतिक संवाद मुख्यतः रैलियों, जनसभाओं, पोस्टरों और पारंपरिक मीडिया के माध्यम से संचालित होता था। अब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म प्रत्यक्ष राजनीतिक संप्रेषण का प्रमुख साधन बन चुके हैं। राजनीतिक नेता ट्विटर पोस्ट, लाइव वीडियो, पॉडकास्ट और डिजिटल अभियानों के माध्यम से सीधे नागरिकों तक पहुँचते हैं।

इस परिवर्तन ने राजनीतिक संचार को अधिक त्वरित और व्यापक बनाया है। सरकारें अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार डिजिटल माध्यमों से करती हैं। नागरिक भी इन माध्यमों के जरिए तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इससे लोकतांत्रिक संवाद का स्वरूप अधिक सहभागी हुआ है।

हालाँकि सत्ता द्वारा डिजिटल माध्यमों का उपयोग केवल संवाद तक सीमित नहीं है। कई बार यह जनमत निर्माण और राजनीतिक छवि-निर्माण का उपकरण भी बन जाता है। डेटा एनालिटिक्स और माइक्रो-टार्गेटिंग के माध्यम से मतदाताओं की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को समझकर राजनीतिक संदेश तैयार किए जाते हैं। इससे चुनावी राजनीति अधिक तकनीक-आधारित हो गई है।

2. पत्रकारिता की बदलती संरचना–

डिजिटल क्रांति ने पत्रकारिता के पारंपरिक स्वरूप को चुनौती दी है। पहले समाचारों का प्रवाह संस्थागत नियंत्रण में होता था, जहाँ संपादकीय प्रक्रिया और तथ्य-जाँच को महत्व दिया जाता था। सोशल मीडिया के उदय के बाद सूचना का प्रवाह विकेंद्रीकृत हो गया। अब कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन और इंटरनेट की सहायता से समाचार प्रसारित कर सकता है।

इस परिवर्तन ने पत्रकारिता को अधिक लोकतांत्रिक बनाया है क्योंकि अब वैकल्पिक आवाज़ों को भी मंच मिला है। अनेक स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल और यूट्यूब चैनल सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नागरिक पत्रकारिता ने स्थानीय समस्याओं और हाशिए के मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श में स्थान दिलाया है।

किन्तु दूसरी ओर पत्रकारिता की विश्वसनीयता संकट का सामना कर रही है। तात्कालिकता और प्रतिस्पर्धा के कारण कई बार अपुष्ट समाचार प्रसारित कर दिए जाते हैं। फेक न्यूज़ और भ्रामक

© Copyright @ Authors

सूचनाएँ समाज में भ्रम और तनाव उत्पन्न करती हैं। डिजिटल माध्यमों में 'पहले प्रकाशित करो, बाद में सत्यापन करो' की प्रवृत्ति पत्रकारिता की नैतिकता के लिए चुनौती बन गई है।

3. सोशल मीडिया और जनमत निर्माण–

जनमत निर्माण लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है। पहले यह कार्य मुख्यतः समाचारपत्रों और टेलीविजन चैनलों द्वारा किया जाता था, परंतु अब सोशल मीडिया इस प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। ट्विटर ट्रेंड, वायरल वीडियो, मीम संस्कृति और ऑनलाइन अभियानों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर व्यापक चर्चा होती है।

सोशल मीडिया ने आम नागरिकों को अभिव्यक्ति का मंच दिया है। अब नागरिक केवल दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदार बन गए हैं। सामाजिक आंदोलनों, जन अभियानों और विरोध प्रदर्शनों में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। अरब स्प्रिंग, निर्भया आंदोलन, किसान आंदोलन और नागरिकता संशोधन कानून के विरोध जैसे आंदोलनों में सोशल मीडिया ने संगठन और प्रचार का कार्य किया।

इसके बावजूद सोशल मीडिया का जनमत निर्माण हमेशा सकारात्मक नहीं होता। एल्गोरिद्मिक संरचनाएँ उपयोगकर्ताओं को वही सामग्री दिखाती हैं, जिससे उनकी पूर्व मान्यताएँ और मजबूत होती हैं। इससे वैचारिक ध्रुवीकरण बढ़ता है। लोग विरोधी विचारों से संवाद करने के बजाय अपने ही वैचारिक समूहों में सीमित हो जाते हैं।

4. सत्ता और मीडिया के संबंधों की जटिलता–

लोकतंत्र में मीडिया का दायित्व सत्ता की निगरानी करना होता है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य जनता के हित में सत्ता से प्रश्न पूछना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। किंतु डिजिटल युग में सत्ता और मीडिया के संबंध अधिक जटिल हो गए हैं।

कई मीडिया संस्थान कॉर्पोरेट स्वामित्व और राजनीतिक हितों से प्रभावित होते हैं। विज्ञापन आधारित अर्थव्यवस्था के कारण मीडिया संस्थानों पर आर्थिक दबाव रहता है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों पर क्लिक और व्यूअरशिप बढ़ाने की होड़ में कई बार समाचारों की गंभीरता कम हो जाती है।

राजनीतिक दलों ने भी अपने डिजिटल नेटवर्क विकसित किए हैं। आईटी सेल, ट्रोल समूह और संगठित ऑनलाइन प्रचार के माध्यम से राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। पत्रकारों और आलोचकों को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, धमकियों और चरित्र हनन का सामना करना पड़ता है। इससे स्वतंत्र पत्रकारिता प्रभावित होती है।

© Copyright @ Authors

5. डिजिटल पत्रकारिता और लोकतंत्र–

डिजिटल पत्रकारिता ने लोकतंत्र को कई स्तरों पर सशक्त बनाया है। सूचना तक पहुँच आसान हुई है। नागरिक अब केवल राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से भी तुरंत अवगत हो जाते हैं। डिजिटल माध्यमों ने पारदर्शिता और जन-जागरूकता को बढ़ावा दिया है।

सरकारी योजनाओं, नीतियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी अब ऑनलाइन उपलब्ध है। इससे नागरिकों की सहभागिता बढ़ी है। ई-गवर्नेंस और डिजिटल संवाद ने शासन को अधिक उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया है।

किन्तु डिजिटल लोकतंत्र की अपनी सीमाएँ भी हैं। इंटरनेट की असमान पहुँच, डिजिटल साक्षरता की कमी और सूचना की अधिकता जैसी समस्याएँ लोकतांत्रिक संवाद को प्रभावित करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए डिजिटल माध्यमों तक समान पहुँच अभी भी चुनौती है।

6. फेक न्यूज़ और सूचना संकट–

डिजिटल युग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक फेक न्यूज़ है। सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएँ अत्यंत तेजी से फैलती हैं। कई बार राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक उद्देश्यों से भ्रामक सामग्री प्रसारित की जाती है। इससे सामाजिक तनाव और हिंसा की घटनाएँ भी उत्पन्न होती हैं।

फेक न्यूज़ केवल सूचना का संकट नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र और सामाजिक विश्वास के लिए भी खतरा है। जब नागरिक सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाते, तब लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है। पत्रकारिता की विश्वसनीयता भी कमजोर होती है।

इस समस्या से निपटने के लिए तथ्य-जाँच संस्थाओं, मीडिया साक्षरता और डिजिटल नैतिकता की आवश्यकता है। सरकार, मीडिया संस्थानों और नागरिक समाज को मिलकर इस दिशा में कार्य करना होगा।

7. पत्रकारिता की नैतिक चुनौतियाँ–

डिजिटल प्रतिस्पर्धा के दौर में पत्रकारिता अनेक नैतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। टीआरपी और क्लिक-आधारित मॉडल ने समाचारों को बाज़ारवादी दृष्टिकोण से प्रभावित किया है। सनसनीखेज़ शीर्षक, भावनात्मक सामग्री और विवादास्पद विमर्श दर्शकों को आकर्षित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं।

पत्रकारिता की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि तथ्य-जाँच, निष्पक्षता और जनहित को प्राथमिकता दी जाए। पत्रकारों को डिजिटल माध्यमों में भी नैतिक मानकों का पालन

© Copyright @ Authors

करना चाहिए। स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र की आत्मा है और इसकी रक्षा सामाजिक उत्तरदायित्व है।

8. नागरिक पत्रकारिता और वैकल्पिक विमर्श–

डिजिटल माध्यमों ने नागरिक पत्रकारिता को नई पहचान दी है। अब आम नागरिक घटनाओं की रिपोर्टिंग कर सकते हैं और सामाजिक मुद्दों को सामने ला सकते हैं। इससे सूचना-प्रवाह अधिक लोकतांत्रिक हुआ है।

नागरिक पत्रकारिता ने कई बार मुख्यधारा मीडिया की सीमाओं को उजागर किया है। स्थानीय समस्याएँ, पर्यावरणीय संकट, मानवाधिकार उल्लंघन और सामाजिक असमानताओं जैसे मुद्दे डिजिटल मंचों के माध्यम से व्यापक चर्चा में आए हैं।

हालाँकि नागरिक पत्रकारिता के साथ विश्वसनीयता और प्रशिक्षण की समस्या भी जुड़ी हुई है। सभी नागरिक पत्रकार तथ्य-जाँच और पत्रकारिता के नैतिक मानकों का पालन नहीं करते। इसलिए इस क्षेत्र में मीडिया साक्षरता और प्रशिक्षण आवश्यक है।

निष्कर्ष :–

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल तकनीक और सोशल मीडिया ने सत्ता तथा पत्रकारिता के संबंधों को गहराई से प्रभावित किया है। राजनीतिक संप्रेषण अब अधिक प्रत्यक्ष, त्वरित और तकनीक-आधारित हो गया है। सोशल मीडिया ने नागरिकों को अभिव्यक्ति और सहभागिता का नया मंच प्रदान किया है, जिससे लोकतांत्रिक संवाद का विस्तार हुआ है। दूसरी ओर पत्रकारिता के समक्ष विश्वसनीयता, निष्पक्षता और नैतिकता की गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। फेक न्यूज़, ट्रोल संस्कृति, कॉर्पोरेट प्रभाव और राजनीतिक ध्रुवीकरण ने मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित किया है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों की तात्कालिकता ने तथ्य-जाँच की प्रक्रिया को कमजोर किया है।

यह भी स्पष्ट है कि डिजिटल पत्रकारिता ने वैकल्पिक विमर्शों और नागरिक पत्रकारिता को बढ़ावा दिया है। इससे लोकतंत्र अधिक सहभागी बना है, किन्तु सूचना-संकट और दुष्प्रचार की समस्याओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी की हैं।

अतः आवश्यक है कि डिजिटल संप्रेषण को लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व और नैतिक पत्रकारिता के सिद्धांतों के अनुरूप विकसित किया जाए। मीडिया साक्षरता, तथ्य-जाँच तंत्र और स्वतंत्र पत्रकारिता को सुदृढ़ बनाना समय की आवश्यकता है। डिजिटल युग में सत्ता और पत्रकारिता का संबंध केवल सूचना के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह लोकतंत्र, जनमत

© Copyright @ Authors

और सामाजिक चेतना के निर्माण की केंद्रीय प्रक्रिया बन चुका है। सोशल मीडिया और डिजिटल पत्रकारिता ने नागरिकों को संवाद और भागीदारी के नए अवसर प्रदान किए हैं। इससे लोकतंत्र का दायरा विस्तृत हुआ है और राजनीतिक संप्रेषण अधिक गतिशील बना है।

किन्तु तकनीक के साथ आने वाली चुनौतियों की अनदेखी नहीं की जा सकती। यदि डिजिटल माध्यमों का उपयोग केवल प्रचार, वैचारिक ध्रुवीकरण और सूचना-हेरफेर के लिए किया जाएगा, तो लोकतंत्र की मूल भावना कमजोर होगी। पत्रकारिता की स्वतंत्रता, तथ्यपरकता और सामाजिक उत्तरदायित्व को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है।

भविष्य में डिजिटल संप्रेषण की भूमिका और भी व्यापक होगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा और एल्गोरिद्मिक संचार राजनीति और पत्रकारिता दोनों को प्रभावित करेंगे। ऐसे में आवश्यक है कि तकनीकी विकास के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की रक्षा की जाए। यही स्वस्थ लोकतंत्र और उत्तरदायी पत्रकारिता की आधारशिला है।

संदर्भ :–

1. चॉम्स्की, नोम एवं हरमन, एडवर्ड : प्रोपेगेंडा मॉडल एंड मीडिया स्टडीज़।
2. हैबरमास युर्गन : द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर।
3. मैक्लुहान, मार्शल : अंडरस्टैंडिंग मीडिया।
4. लासवेल हेरॉल्ड : पॉलिटिक्स एंड कम्युनिकेशन।
5. कुमार के.जे., जनसंचार माध्यम, सिद्धांत एवं व्यवहार।
6. शर्मा रामगोपाल, भारतीय पत्रकारिता का इतिहास।
7. सरदेसाई राजदीप, 2014, द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया।
8. गुहा रामचंद्र, भारत : गांधी के बाद।
9. प्रसून, पुण्य, मीडिया और लोकतंत्र।
10. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्टें।
11. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट।

© Copyright @ Authors